आरा-मोहनियां सड़क के नवनिर्माण का रास्ता साफ

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

आरा- मोहनियां सड़क के दिन अब बहुरते दिख रहे हैं। सड़क को लेकर केन्द्र सरकार की शर्त राज्य सरकार ने मान ली। कोर्ट के फैसले के बाद अगर सरकार पर कुछ लायबिलिटी तय हुई तो राज्य सरकार उसका वहन करेगी। राज्य सरकार की सहमति मिलते ही केन्द्र इस सड़क के नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

राज्य सरकार द्वारा शर्त मान लेने के बाद यह सड़क केन्द्र सरकार अपने पास वापस ले लेगी। इसके बाद इसके फोरलेन बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार ने सड़क को केन्द्र सरकार को सौंपने का फैसला पहले ही कर लिया था। चूंकि पहली निर्माण एजेन्सी के साथ सरकार का मामला कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा लायबिलिटी को लेकर मामला फंसा हुआ था। केन्द्र का कहना था कि अगर कोर्ट ने कुछ लायबिलिटी तय की तो उसकी देनदारी राज्य सरकार की होगी। केन्द्र की इसी शर्त पर मामला सालभर से फंसा हुआ था।

पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि राज्य सरकार लायबिलिटी वहन करने को तैयार है। ऐसे में अब इस सड़क के नवनिर्माण में कोई बाधा नहीं है। केन्द्र को वापस होते ही सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केन्द्र सरकार ने इसे फोरलेन बनाने का जिम्मा पहले राज्य सरकार को सौंप था। राज्य सरकार ने निर्माण के लिए टेंडर जारी कर एजेन्सी का भी चयन कर लिया। लेकिन किसी कारण से एजेन्सी के साथ राज्य सरकार का करार खत्म हो गया। लिहाजा सड़क को फोरलेन बनाने का मामला अटक गया। हालांकि बाद में निर्माण का मामला फंसा तो राज्य सरकार ने तत्काल इसकी मरम्मत करने का आग्रह केन्द्र से किया। सरकार ने लगभग 125 किमी लंबी इस सड़क की मरम्मत के लिए 90 करोड़ का स्टीमेट भी केन्द्र सरकार को भेजा था। लेकिन केन्द्र ने सड़क को ही वापस करने को कह दिया। साथ में शर्त भी लगा दी।

फोरलेन बनेगा

- सड़क को लेकर राज्य सरकार ने मानी केंद्र की शर्त
- राज्य से वापस लेकर केन्द्र करेगा नवनिर्माण

125 किमी लंबी है सड़क, 4 साल से अटका है निर्माण कार्य